

हृद-डुरशरररर आरुथक डररर

डुरलडडररर के लडडर:

हृद-डुरशररर, कुररर, सीईडीई (वुडरडक आरुथक डरररडररी डडरररुते)

डुनरर के लडडर:

डररर को शररलल और/डर इसके के हृतरर को डुरडरररर कररने वररने वररने डडररु और डडरररुते, दुवडरकषुड डडररु और डडरररुते, कुररर, हृद-डुरशररर और इसकर डडररुतुव

कररर डुन कुररर?

हृल ही डुन वररररुड और उदुडुड डुनररी ने अडुेरकरर डुन 'हृद-डुरशररर आरुथक डररर' (Indo-Pacific Economic Framework- IPEF) डुनररररररुड डुठक को डुडुधतर कडर, डररर डररर ने नडुडकष और लररुले वुडररर डुतुड से दूर रहने कर डुसलर कडर।

- डररर करर डुतुडुन डुन से तरर डुर डडररुत हुआ, जो आडुररुत शुरुडलर, करर और डुरररुडररर वरररुधुी और डुवकुरु कुरुडर डुन।

हृद-डुरशररर आरुथक डररर (IPEF):

- डरर अडुेरकरर के नेतुतुव वररुी एक डुरल है डररकर उदुदेशुड हृद-डुरशररर कषुतुड डुन लररुलरडन, डुथररतर, डडररेशतर, आरुथक वकडरर, नडुडकषुतुड और डुररररुडडुदुधरतुडककर डडररने के लडडर डररर लेने वररने देशुन के डुीक आरुथक डरररुधुी को डररुडुत कररने है।
- IPEF को 12 देशुन के डुररररुडक डररररुधुी के डरर लुनरु कडर डरर डरर डररुडकषुी डुर से वशुव डकल डररुलु उतुडरड डुन 40% की हडुसरुडररी ररखते डुन।
- IPEF एक डुडकत वुडररर डडरररुतुड (FTA) नुनरुी है, लेकनर डडररुडुन को उन हडुसरुडुन डुर डरररुतुड कररने की अनुडुतुडररुतुड है जो वे कुररते डुन। IPEF के करर डुतुडुन डुन:
 - आडुररुतुड-शुरुडलर डुररुतुडररुथतर/लररुलरडन
 - डुवकुरु कुरुडर, डुीकररडुनरुडररुडररुडन और आडररडुत डुररररुतुड
 - करररधरन और डुरररुडररर वरररुधुी डुरल
 - नडुडकषुतुड और लररुलर वुडररर।
- वररुतुडरन डुन डररर और डुरशररर डररररुडर डुन डुथतर 13 देश इसके डडररुडुन डुन।
 - ऑरुदुरेलडर, डुरुनेरुडु, डररुी, डररर, इंडुनरेशररुडर, डरररन, दकषणरुडर, डररेशररुडर, नुडुीरुीलुड, डररुीडुडर, डररुडर, डररुीलुड, डुडुडकत रररुडुड अडुेरकरर और वडररुतुडरन।

13 economies and China



IPEF पर भारत की स्थिति

- जबकि कुछ देशों ने वार्ता में शामिल होने में रुचि व्यक्त की थी, भारत ने कुछ समय के लिये एक नश्चिति स्थिति की घोषणा नहीं की क्योंकि इसका मानना है कि सदस्य देशों को क्या लाभ मिलेगा और क्या पर्यावरण जैसे पहलुओं पर कोई शर्त वकिसशील देशों के साथ भेदभाव कर सकती है।
- IPEF में प्रस्तावित कुछ क्षेत्र भारत के हित की पूर्ति करते प्रतीत नहीं होते हैं।
 - उदाहरण के लिये, IPEF डिजिटल गवर्नेंस का समर्थन करता है लेकिन IPEF सूत्रीकरण में ऐसे मुद्दे शामिल हैं जो सीधे तौर पर भारत की घोषित स्थिति के साथ टकराव उत्पन्न करते हैं।
- भारत विशेष रूप से गोपनीयता और डेटा के संबंध में अपने स्वयं के **डिजिटल ढाँचे और कानूनों को मज़बूत करने की प्रक्रिया में है।**
 - अगस्त 2022 में भारत सरकार ने व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम को संसद से यह कहते हुए वापस ले लिया कि वह समग्र इंटरनेट पारिस्थितिकी तंत्र, साइबर सुरक्षा आदि को वनियमिति करने के लिये **"व्यापक कानूनी ढाँचे"** पर विचार करेगी।
- अमेरिका ने पहले भारतीय पक्ष द्वारा डेटा स्थानीयकरण या भारत में स्थिति सर्वरों में भारतीय उपयोगकर्ताओं के डेटा के भंडारण और प्रसंस्करण की मांग की संभावना के बारे में, यहाँ तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका-आधारित कंपनियों के डेटा के मामले में भी चिंता व्यक्त की है।
 - अमेरिकी रिपोर्ट ने संभावना व्यक्त की है कि भारत की यह नीति डिजिटल व्यापार के लिये महत्वपूर्ण बाधा के रूप में काम करेगी और विशेष रूप से छोटी फर्मों के लिये बाज़ार पहुँच बाधा के रूप में कार्य करेगी।

अन्य व्यापार सौदों से अलग:

- IPEF वास्तव में एक व्यापार समझौता नहीं है और कई सतंत्रों का प्रावधान प्रतभागियों के लिये यह चुनने का विकल्प प्रदान करता है कि वे किसका हिससा बनना चाहते हैं।
- अधिकांश बहुपक्षीय व्यापार सौदों की तरह यह इसमें शामिल होने या छोड़ने की व्यवस्था नहीं है।
- चूँकि IPEF एक नयिमिति व्यापार समझौता नहीं है इसलिये **सदस्य हस्ताक्षरकर्त्ता होने के बावजूद सभी चार सतंत्रों के लिये बाध्य नहीं हैं।**
 - इसलिये व्यवस्था के व्यापार भाग से दूर रहते हुए, भारत बहुपक्षीय व्यवस्था के अन्य तीन सतंत्रों - आपूर्ति शृंखला, कर और भ्रष्टाचार वरिधी तथा स्वच्छ ऊर्जा में शामिल हो गया है।

हृदि-प्रशांत क्षेत्र पर भारत का दृष्टिकोण:

- इस क्षेत्र में भारत का व्यापार तेज़ी से बढ़ रहा है, वृदिशी निवेश को पूर्व की ओर नरिदेशित किया जा रहा है, उदाहरण के लिये जापान, दक्षिण कोरिया और सगिापुर के साथ **व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते** तथा **आसियान (दक्षिणपूर्व एशियाई राष्ट्र संघ)** एवं थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौते।
- भारत एक स्वतंत्र और खुले हृदि-प्रशांत का सक्रिय समर्थक रहा है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा आसियान के सदस्यों ने इस क्षेत्र में भारत की बड़ी भूमिका को लेकर समान विचार व्यक्त किया है।
- भारत अपने **क्वाड भागीदारों** के साथ हृदि-प्रशांत में अपने प्रयासों को आगे बढ़ा रहा है।
- भारत का विचार हृदि-प्रशांत क्षेत्र में अन्य समान विचारधारा वाले देशों के साथ मिलकर काम करना है ताकि नयिम-आधारित बहुध्रुवीय क्षेत्रीय व्यवस्था का सहकारी प्रबंधन किया जा सके तथा **किसी एक शक्ति को इस क्षेत्र या इसके जलमार्गों पर हावी होने से रोका जा सके।**

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ):

प्रश्न. भारत-प्रशांत महासागर क्षेत्र में चीन की महत्त्वाकांक्षाओं का मुकाबला करना नई त्रि-राष्ट्र साझेदारी AUKUS का उद्देश्य है। वर्तमान परदृश्य में AUKUS की शक्ति और प्रभाव की वविचना कीजिये। (मेन्स-2021)

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस